

संपादकीय

5 हजार सरकारी स्कूल बंद करके, विश्व गुरु बनेगा भारत?

उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार के इस कदम से राज्य में तीन लाख पचास हजार से ज्यादा छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली एक कुशल कार्यबल, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। चैकिं इस देश में प्राथमिक शिक्षा को राजनीतिक ऐंडें में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा अबादी वाला यह देश अभी भी निरक्षरता और खराब शिक्षा से जड़ा रहा है। हाल ही में प्रकाशित आठवीं इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे देश में, जहाँ धर्म और धार्मिक पहचान जनता और सरकार दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, 50 प्रतिशत से ज्यादा स्नातकों का रोज़गार के योग्य न होना कोई आश्वर्य की बात नहीं है। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बताया था कि पिछले 10 साल में यूनेस्को में 89 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इनमें से अधिकांश 25 हजार स्कूल अर्कले उत्तर प्रदेश से थे। 5 हजार स्कूल और बंद हमारे दिल पर मोर लोड ना आए इसलिए योगी सरकार ने स्कूल बंद करने की इस स्कॉच को नाम दिया है पेअरिंग स्कॉच। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख 62 हजार प्राथमिक विद्यालय थे। जो साल 2021-22 में 1 लाख 40 हजार ही रह गए। यानी 2015-16 के मुकाबले में ये संख्या कम हो गई। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन्हें बंद कर देना ही बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्कॉटिश बच्चे क्यों नहीं हैं? क्या बच्चों की संख्या आपके-आप कम हो गई, या इसके पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं? ईटीवी-भारत न्यूज वेबसाइट के अनुसार यू-डीआईएसडी पोर्टल के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं, वो देखने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 30,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जो जर्जर स्थिति में हैं। जहां 742 स्कूल पूरी तरह से खराब खंडहर हैं। इसके बाद 690-690 में जंगल और जंगल में 674, ग़रीब में 643, 641 में ग़रीब में और 633 में बलिया में कब्ज़ा की स्थिति बेहद खस्ता है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए न तो अधूरा निर्माण है, न शौचालय, न पीने का पानी और न ही चारदीवारी। कभी मिड-डे मील का सामान नहीं आता, तो कभी छत टपकती है। स्थानीय बिजली नहीं। कभी-कभी स्कूल में ही जूते ढूब जाते हैं। तो ऐसे रसोई में किसी ने भी अपने बच्चों को क्यों भेजेगा? जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? जिन शिक्षकों में शिक्षक तैनात हैं, वहां उनकी इयूटी चुनाव, सर्वेक्षण, योजना या धार्मिक आयोजनों में लगाई जाती है। स्कूल सिर्फ रिकॉर्ड में है। कलासरसम बंद होता है, परिसर सूना रहता है। फिर जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, तो परिवार वाले अपने बच्चों को या तो प्राइवेट स्कूलों में दाल देते हैं या फिर पढ़ाई ही छुड़वा देते हैं। यानी धीरे-धीरे सरकारी स्कूल के बच्चे आना ही बंद कर देते हैं। फिर एक दिन शासन की रिपोर्ट आती है छात्र संख्या कम है, स्कूल बंद कर दिया जाएगा। बाकी जो स्कूल चल रहे हैं उनमें भी बार-बार सुरक्षा के नाम पर छुट्टियां घोषित कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अब बस एक धार्मिक परंपरा नहीं रही, ये एक सरकारी आयोजन संस्था बन चुकी है। हर साल जैसे ही सावन आता है, प्रदेश का पारा सरकारी तंत्र एक ही दिशा में दौड़ता है- तीरथायात्रियों की सेवा। स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक, स्वास्थ्य विभाग से लेकर नगर निगम तक, हर विभाग को आदेश दिया जाता है कि कंकांवड़ियों की सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कंजगह-जगह कैंप, मैडिकल कैंप, मोबाइल स्टेडियम, मिस्टर फैन, नमक-पानी तक डाला जाता है।

ट्रम्प प्रशासन भारतीय दर्शन को अपनाकर वैश्विक समरयाओं का हल निकाल सकते हैं

प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर आज की आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत का प्राचीन आर्थिक दर्शन संभवतः आशा की किरण के रूप में दिखाई पड़ता है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, अपने अहंकार के मद में, जब अपने पड़ोसी देशों एवं हितचिंतक देशों के साथ ही अन्य अविकसित एवं विकासशील देशों को भी नहीं बक्ष रहा है एवं इन देशों से अमेरिका को होने विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर टैरिफ़ का डंडा चला रहा है, तब भारतीय आर्थिक दर्शन की वसुधैव कुटुबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एवं सर्व भवतु सुखिन सर्व सत्ता निरामयाः जैसी नीतियों की याद सहज रूप से ही आ जाती है। भारतीय आर्थिक दर्शन की अनुसार, अर्थ का अर्जन करना बुरी बात नहीं है परंतु इसका धर्म के अनुसार उपयोग नहीं करना बुरी बात है। ट्रम्प प्रशासन की वर्तमान नीतियों से स्पष्ट झलकता है कि अथाह मात्रा में इकट्ठे किए गए धन का उपयोग विश्व के अन्य देशों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका आज कई देशों पर दबाव बनाता हुआ दिख रहा है कि यदि किसी देश ने उसकी शर्तों के अनुरूप अमेरिका के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौता नहीं किया तो उस देश से होने वाले वस्तुओं के अमेरिका में आयात पर भारी मात्रा में टैरिफ़ लगाया जाएगा।

यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्व के कई देश विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और आज यह सम्पन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इन देशों के नागरिकों को भौतिक सुख की प्राप्ति तो हुई है परंतु उनके जीवन में मानसिक सुख का पूर्णता अभाव है। अतः इनके जीवन में संतोष का

मनसा का मातमः अफवाह बनी त्रासदी की वजह

ललित गर्ज

हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में बिजली का तार टूटने और करंट फैलने की एक अफवाह ने कई जानें ले लीं, जिसने धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। किसी धार्मिक स्थल पर भगदड़ की यह पहली घटना नहीं, लेकिन अफसोस है कि पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया जा रहा। ऐसी त्रासद, विडबनापूर्ण एवं दुखद घटनाओं के लिये मन्दिर प्रशासन और सरकारी प्रशासन जिमेदार हैं, रविवार की सुबह एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिये मौत का मातम बनी, चीख, पुकार और दर्द का मंजर बना। लगभग साढ़े आठ से नौ बजे के बीच हजारों श्रद्धालु संकीर्ण सीढ़ीदार मार्ग से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही अचानक करंट लगने की अफवाह ने अफरा-तफरी का माहौल बनाया, श्रद्धालु घबराहट में एक-दूसरे पर गिरने लगे और कुछ ही पलों में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि करीब तीस श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर थी।



भगदड़ में लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई, उसका दर्द समूचा देश महसूस कर रहा है। प्रश्न है कि पुलिस का बंदोबस्त कहां था? श्रद्धालुओं की मौत एक ऐसा दर्दनाक एवं खौफनाक वाकया है जो सुर्दीर्घ काल तक पीड़ित और परेशान करेगा। प्रशासन की लापरवाही, अत्यधिक भीड़, निकासी मार्गों की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में सामने आई ऐसी घटनाओं की कड़ी का नया खौफनाक मामला है, जहां भीड़ नियंत्रण में चूक एवं प्रशासन एवं सत्ता का जनता के प्रति उदासीनता का गंभीर परिणाम एवं त्रासदी का ज्वलंत उदाहरण है। मनसा के मातम, हाहाकार एवं दर्दनाक मंजर ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल ही नहीं खोली बल्कि सत्ता एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है। भारत में भीड़ से जुड़े हादसे आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहां भीड़

प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, पिछले एक साल पर नजर दौड़ाइं तो इस तरह के कई दुखद हादसे हो चुके हैं। हाल ही में पुरी में भगदड़ जानलेवा साबित हुई। पिछले साल जुलाई में ही हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस साल जनवरी की शुरुआत में तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के लिए हृद से ज्यादा श्रद्धालु पुहंच गए और पुलिस उनको काबू नहीं कर सकी। भगदड़ मची तो 6 लोगों की जान चली गई। इसी साल, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के रत्नागढ़ मंदिर में ढाँचात तकमियों से प्रेरित भगदड़ के कारण 115 लोगों की मौत हो गई थी।

भारत हा नहा दुनिया मध्यामक आयाजना मध्यांभाड प्रबंधन हमेशा से बडी चुनौती बनता रहा है। वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटावन हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में मक्का में हज

के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। आग, भूकंप, या आतंकी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों में भी भीड़ प्रबंधन की पौल खुलती रही है। आखिर दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में हम भीड़ प्रबंधन को लेकर इतने उदासीन क्यों हैं? बड़े आयोजनों-भीड़ के आयोजनों में भीड़ बाधाओं को दूर करने के लिए भीड़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार, सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जन जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अब नितान्त आवश्यक है। हर बार जांच, कठोर कार्रवाई करने, सबक सीखने की बातें की जाती हैं, लेकिन नतीजा के ढाक के तीन पात वाला है। न तो शासन-प्रशासन कोई सबक सीख रहा है और न ही आप जनता संयम एवं अनुशासन का परिचय देने की आवश्यकता समझ रही है। भगदड़ की घटनाओं का सिलसिला कायम रहने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी भी होती है, क्योंकि इन घटनाओं से यही संदेश जाता है कि भारत का शासन-प्रशासन भगदड़ रोकने में पूरी तरह नाकाम है। सार्वजनिक स्थलों पर भगदड़ की घटनाएं दुनिया के अन्य देशों में भी होती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपने देश में होती ही रहती हैं। क्या इस तरह की अफवाह को रोका नहीं जा सकता था? हमारा प्रशासन कोई अनुमान लगाने में इतना अक्षम क्यों है? क्या इसका कारण उसकी संवेदनहीनता है अथवा यह कि संबंधित अधिकारी यह जानते हैं कि कैसी भी घटना हो जाए, उनका कुछ नहीं बिंगड़ने वाला। आखिर हम दुनिया के अन्य देशों से कोई सबक सीखने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की कोई ठोस और वैज्ञानिक व्यवस्था है? मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियां, संकरे रास्ते और अव्यवस्थित ढूकानों के बीच का क्षेत्र लंबे समय से भीड़भाड़ के लिए जाना जाता है। फिर भी वहां कोई स्थायी सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए? अफवाह पर नियंत्रण के लिए कोई त्वरित सूचना तंत्र नहीं था, न ही भीड़ को दिशा देने के लिए पर्याप्त पुलिस बल या मार्गदर्शन की व्यवस्था थी। इस तरह की घटनाएं केवल अफवाह का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि यह व्यवस्था की कमजोरियों एवं कोताही का परिणाम होती हैं। तीर्थस्थलों पर नियंत्रित प्रवेश, डिजिटल टिकटिंग, सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन निकासी मार्ग, और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय मौजूदगी जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होनी चाहिए। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भगदड़ की घटनाएं लगभग वैसे ही कारणों से रह रहकर होती रहती हैं, जैसे पहले हो चुकी होती हैं।

मृतकों में उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखण्ड के लाग शामिल थे। उनमें छह वर्षीय बच्चा आरुष, किशोर और बुजुर्ग तक शामिल थे। उनके परिवारों पर अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस दौरान बचे हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि भीड़ इतनी घनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मनसा देवी मंदिर की यह घटना हमें याद दिलाती है कि भीड़ सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि अगर उसे सही दिशा और सुरक्षा नहीं दी जाए तो वह भयावह त्रासदी में बदल सकती है। यह समय है कि प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट और समाज मिलकर ठोस कदम उठाएं ताकि आस्था के केंद्र जीवन के लिए खतरा न बनें। तमाम धार्मिक स्थलों पर फैली अव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिसलन भरे रास्ते, संकरी जगह, आने-जाने का एक ही मार्ग जैसी बातें लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में जब किसी खास मौके पर भीड़ बढ़ती है तो स्वाभाविक ही हादसे की आशंका भी बढ़ जाती है, जैसा सावन पर मनसा देवी में हुआ। बेंगलुरु में आरसीबी के इक्वेंट में हुए हादसे के बाद कर्नाटक सरकार क्राउड कंट्रोल पर एक बिल लेकर आई है, जिसमें जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ऐसे कानून की हर जगह जरूरत है। रेलवे स्टेशन, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त जगह और रास्ते नहीं हैं। कुछ स्थानों पर निकास मार्ग सीमित हैं या अनुपयुक्त हैं, जो भगदड़ का खतरा बढ़ाते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित एवं दक्ष सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा चूक होने की संभावना बढ़ जाती है।



देशों के नागरिक खाने पीने की वस्तुओं, अच्छे वस्त्रों, बड़े एवं सुविधाजनक निवास स्थान, मनोविनोद के साधनों में वृद्धि, वासना की वृद्धि एवं वासना की संतुष्टि के लिए विभिन्न साधनों में वृद्धि, सुख के लिए उपभोग में वृद्धि जैसे कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। जैसे इस धारा पर जीवन जीने का लक्ष्य यही है। इच्छाओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। एक डच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह पूँजीवाद में निहित पश्चिमी विचार है। इस धारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक

पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवत्कर) कहते हैं कि खण्डश्चिम के सुख की अवधारणा पूर्णतया प्रकृति जन्य इच्छाओं की संतुष्टि पर केंद्रित है, अतः उनके जीवन स्तर को उठाने का अर्थ भी केवल भौतिक आनंद की वस्तुओं को अधिकाधिक जुटाना है। इससे व्यक्ति अन्य विचारों एवं एषणाओं को छोड़कर केवल इसी में पूर्णतया संलग्न हो जाता है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की इच्छा धन संग्रह को जन्म देती है। अधिकाधिक धन प्राप्ति हेतु शक्ति आवश्यक हो जाती है; किंतु भौतिक सुख की अत्रस क्षधा व्यक्ति को अपनी राशीय

बिना रेता परमीशन के भू माफियाओं के द्वारा करोड़ों की भूमि में अवैध प्लाटिंग का खेल

सीएमओ ने नोटिस जारी कर शुरू की कार्यवाही

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मनगवां नगर परिषद क्षेत्र में लगातार बिना किसी परमिशन के अंधाधुंध नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग कर अवैध कालोनी बसाए जाने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद से यहाँ का नगर परिषद सख्त हो गया है नगर परिषद के द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर के कालोनी बसा रहे मालिकों को नोटिस देकर जारी करते हुए बनाए जा रहे अवैध कालोनी को रोके जाने के लिए कहा गया है। नगर परिषद के बोर्ड नंबर 14 में 82/2/1 एवं 83/1/41 व 83/41/31 के भू स्वामियों के द्वारा मनगवां नगर परिषद में सबसे बड़ी प्लाटिंग कर कालोनी की बसाह कराई रही है वहीं इस मामले को



नगर परिषद ने गंभीरता से लिया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमन्त त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है की नियम विरुद्ध तरीके से बसाहट कराने वाले कोलोनाइजर के प्रोप्रिएटरों को नोटिस जारी कर दी गई है मनगवां के बाईं क्रमांक 14 में सबसे

24 जुलाई को बीसी में नगरीय प्रशासन के पीएस के द्वारा निर्देशित किया गया है की जो लोगों द्वारा रेकी नियमों का बिना लालन स्वीकृति के प्लाटिंग कालोनी बना कर बेची जा रही है उसपर नगरपालिका कार्यवाही करे।

प्लाटिंग भूमि की बिक्री 1 से 2 हजार के बीच लेकिन रजिस्ट्री सरकारी रेट 500 रु के आसपास की: जानकारी के अनुसार मनगवां में अवैध रूप से स्प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री के खर्च में सरकार के टैक्स की भी चोरी की जा भूमि क्रेताओं के द्वारा 1 से 2 हजार रुपए प्रति स्कायर फिल के हिसाब से सौदा करते हैं लेकिन उन्हें रजिस्ट्री 500 रु के आस पास जो भी सरकारी रेट है उसके अनुसार रजिस्ट्री करा कर टैक्स चोरी का खेल किया जा रहा है। को नोटिस जारी करते हुए मौके में चर्चा कराया गया है। बताया

जाता है की यहाँ पर लगभग 04 एकड़ ज्ञानीय स्थानों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखा यह: मनगवां नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया ने यहाँ पर अवैध रूप से भूमाफियाओं के द्वारा प्लॉटिंग का कारोबार किए जाने पर रोक लगाए जाने के लिए रीवा कलेक्टर प्रतिभाव पाल एवं रोके के प्रमुख सचिव मप्र भोपाल के प्रति व्यापारी को यहाँ पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा प्लॉटिंग का कारोबार किया जा रहा है साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों की निजी जानीय भी प्रभावित की जा रही है। प्लॉटिंग करने वाले लोगों के द्वारा शासकीय व गैर शासकीय जानीयों को हाथरायने का भी काम किया जा रहा है ऐसी स्थिति में जननित को देखते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ सकृदार्थ कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अधिकवाक बीके माला ने बताया कि असामाजिक तत्व बेलगाम हो चुके हैं और उनमें पुलिस-प्रशासन का कोई भय नहीं रहा। उन्होंने व्यांग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि अब शहर के सार्वजनिक स्थलों को प्रभावित कर रही है।

दबंगों ने स्कूल में घुसकर प्राचार्य को पीटा, 10 बदमाशों पर एफआईआर, पहले स्कूली छात्र से हुआ था विवाद

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले के बिछिया थाना के लक्ष्मणपुर में संचालित राजहंस शिशु विद्यालय में सोमवार का पुलिस ने दबंगों के द्वारा घुसकर प्राचार्य को पीटा, 10 बदमाशों पर एफआईआर दर्भार लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

गाली-गलौज कर और लड़कों को बुलाया: समझाइश के बाद भी चारों युवक नहीं माने और गाली-गलौज करते हुए फोन कर लगाया।

<p